

2

हरियाणा-दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के आसार

4

मनरेगा खत्म, 'जी राम जी' योजना लागू

9

सकल जीएसटी संग्रह जून में 13.9 प्रतिशत बढ़ा

11

मेक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराया



1934 से

एक नजर में



जन्मजात नागरिकता के खिलाफ काम करे संसद
वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जन्म के आधार पर नागरिकता उनके देश के लिए अच्छी नहीं है और वह इसके खिलाफ जल्द ही संसद में कानून देखना चाहेंगे. श्री ट्रंप ने मंगलवार रात टरुथ सोशल पर लिखे एक पोस्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को बरकरार रखा है, जो हमारे देश के लिए बहुत बुरा है. हम राष्ट्रपति के समर्थन से संसद में कानून लाकर इसमें बदलाव कर सकते हैं. इस प्रक्रिया के दौरान अब यह तय हो गया है.

गुरुद्वारे गिराने पर भारत ने पाक से मांगा जवाब
नई दिल्ली. भारत ने पाकिस्तान में 125 साल पुराने गुरुद्वारे को गिराए जाने को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है और इस मामले को जांच कराने तथा दोषियों को सजा देने की मांग की है. विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रकाशण रीणीय जायसवाल ने इस संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में बुधवार को कहा कि मंत्रालय ने पाकिस्तान के फारूकबाद में ऐतिहासिक, 125 साल पुराने पवित्र गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह साहिब को गिराए जाने के बारे में बेहद परेशान करने वाली खबरें देखी हैं. उन्होंने कहा, हम सिखों के इस सम्मानित धार्मिक स्थल के खिलाफ तोड़-फोड़ की इस बेहद निंदनीय और जानबूझकर की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं.

चुनौती देते हुए अंतरिम राहत की मांग
नई दिल्ली. तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें बकरीद वाले दिन सहित पूरे राज्य में कहीं भी गाय या बछड़े के वध पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार का तर्क है कि उच्च न्यायालय अपने समक्ष आयी याचिका के दायरे से बहुत आगे निकल गया है. यह याचिका केवल कोयंबटूर में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गायों के वध को रोकने तक ही सीमित थी. उच्च न्यायालय ने गत 27 मई को इस आशय का निर्णय दिया था. पशुपालन, डेवरी, मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण विभाग के सचिव की ओर से दायर इस अपील में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने राज्य के वैधानिक ढांचे के विपरीत निर्देश जारी किये हैं.

एसआईटी को मिला 15 तक और समय
लखनऊ. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को शासन ने और समय दे दिया है. अब विशेष जांच टीम 15 जुलाई तक अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी. पहले यह रिपोर्ट 30 जून तक देनी थी. जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है. एसआईटी प्रमुख, लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के सदस्यों किरण एस. और वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरत्न कुमार के साथ प्रारंभिक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी थी. प्रारंभिक रिपोर्ट में ही एसआईटी ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय और अधिकारियों की मांग की थी.

बस में आग से 8 जिंदा जले

इंदौर की छात्रा समेत 8 की मौत, 21 लोग घायल

नव भारत न्यूज
इंदौर, 1 जुलाई. घर लौटने की खुशी कुछ ही पल में मातम में बदल गई. राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात ऋषिकेश से इंदौर आ रही स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर से टकराने के बाद आग की लपटों में घिर गई. देखते ही देखते पूरी बस धधक उठी और कई यात्री बाहर निकलने से पहले ही आग की चपेट में आ गए. हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 यात्री घायल हैं.

मृतकों में इंदौर की इंजीनियरिंग छात्रा भूमि भोर भी शामिल हैं, जबकि शहर की निर्मला गुप्ता का देर रात तक कोई सुराग नहीं मिल सका. हादसा रात करीब ढाई बजे कोलवा थाना क्षेत्र के तनावड़ जीरो पॉइंट पर हुआ. प्रारंभिक जांच में बस के तेज रफ्तार होने और चालक को झपकी आने की आशंका जताई जा रही है. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रेलर दोनों में आग लग गई. पुलिस सूत्रों के मुताबिक छह यात्रियों की मौत झुलसने से हुई, जबकि दो ने गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया. हादसे में इंदौर के मेघदूत नगर निवासी 20 वर्षीय भूमि भोर एलएनटी कॉलेज में



इंदौर के कई यात्री घायल ...

हादसे में इंदौर के कई यात्री भी घायल हुए हैं. इनमें दिशा, याचिका, नेहा, सुवानंद, प्रदीप, महक, योगानी और चंद्रप्रकाश गुप्ता शामिल हैं. सभी का उपचार दौसा जिला अस्पताल में चल रहा है, जबकि कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.



इंदौर के कई यात्री घायल ...

पहुंची. सूत्रों के हवाले से दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने भी दावा किया है कि हादसे के दौरान बस का इमरजेंसी गेट नहीं खुला, जिससे कई यात्री बाहर नहीं निकल सके. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

घटनास्थल पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने बस की डिक्की में

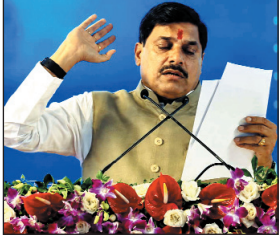
मुख्यमंत्री ने दी करोड़ों की सौगात

2.82 करोड़ की प्रोत्साहन राशि किसानों के खातों में भेजी

494 करोड़ की 629 विकास कार्यों का किया लोकार्पण

सिवनी, 1 जुलाई. मुख्यमंत्री ने बुधवार को सिवनी के पॉलिटेक्निक मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव एवं किसान सम्मेलन में जिले को विकास की बड़ी सौगात दी.

इस अवसर पर लगभग 494 करोड़ की लागत के 629 विकास



कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया तथा प्रदेश के 3,941 कोदो-कुटकी उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 22.82 करोड़ की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की गई. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों को आय बढ़ाने, प्राकृतिक

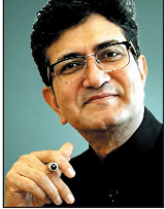
खेती को प्रोत्साहित करने और श्रीअन्न (मिलेट्स) को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष बताते हुए किसानों से आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और श्रीअन्न के उत्पादन में वृद्धि करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिवनी जिले के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।

(शेष पेज 12 पर)

प्रसून जोशी को मिलेगा पहला एनबीटी भूषण सम्मान

नई दिल्ली, 01 जुलाई. प्रख्यात लेखक, गीतकार और पटकथा लेखक प्रसून जोशी को 4 जुलाई को आयोजित होने वाले एनबीटी उत्सव 2026 में पहली बार दिए जा रहे 'एनबीटी भूषण सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा।

साहित्य, संस्कृति, रचनात्मकता और जनसंचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं दीर्घकालिक योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से इस सम्मान की शुरुआत की है. प्रसून जोशी को यह सम्मान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई



दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान करेंगे. रचनात्मक दुनिया का बड़ा नाम- प्रसून जोशी

देश के उन चुनिंदा रचनाकारों में शामिल हैं, जिनकी लेखनी ने सिनेमा से आगे बढ़कर उम्मीद, संवेदनाओं, देशभक्ति और सामाजिक बदलाव की आवाज़ को अभिव्यक्ति दी है।

सुरक्षित पैसे भेज सकते हैं कस्टमर्स

डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के वैश्विक विस्तार में एक और अहम पड़ाव है

नई दिल्ली, 01 जुलाई. भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आधिकारिक तौर पर ग्रीस में लॉन्च हो गया है. केंद्रीय वाणिज्य पीयूष गोयल ने मंगलवार को एंथेंस में यूरोबैंक के मुख्यालय में यूरोबैंक और एनआईपीएल की साझेदारी के तहत यूपीआई सेवाओं के लाइव प्रदर्शन को देखा.

इस मौके पर उनके साथ यूरोबैंक के सीईओ फोकियन कारावियास और फेयरफेक्स डिजिटल सर्विसेज के सीईओ संजय तुगनायत भी मौजूद थे. केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि यह



लॉन्च भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के वैश्विक विस्तार में एक और अहम पड़ाव है. उन्होंने कहा कि ग्रीस में यूपीआई के शुरू होने से, योग्य ग्राहक तुरंत, सुरक्षित और

आसानी से पैसे हस्तांतरित कर सकते हैं. साथ ही, पैसे हस्तांतरित करने के पारंपरिक तरीकों की तुलना में लेनदेन की लागत भी बहुत कम हो गई है.

कोई भी व्यवस्था न्यायालय से ऊपर नहीं : हाईकोर्ट

जबलपुर, 1 जुलाई. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने न्यायिक जवाबदेही पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति या व्यवस्था न्यायालय से ऊपर नहीं हो सकती।

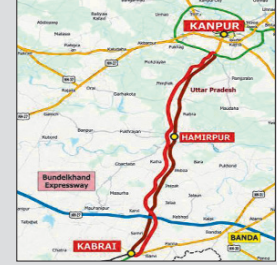
न्यायालय ने उक्त टिप्पणी उस समय की, जब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन की ओर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी गई और उनके हलफनामे का स्पष्टीकरण

अधिवक्ता द्वारा देने की पेशकश की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन प्रश्नों का संबंध सीधे चेयरमैन के हलफनामों से है, उनका उत्तर उन्हें स्वयं देना होगा। आदेश में अदालत ने दर्ज किया कि प्रस्तुत तर्कों से ऐसा प्रतीत होता है मानो संबंधित अधिकारी न्यायालय से ऊपर हों, जबकि यह कार्यप्रणाली स्वीकार्य नहीं है। दरअसल यह मामला आयकर अधिकारी सुधीर कुमार गुप्ता की याचिका से जुड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति को चुनौती दी गई है।

कैबिनेट बैठक दो साल में पूरा होगा 242 किलोमीटर का प्रोजेक्ट

कानपुर से भोपाल हाईवे को मिली मंजूरी

नई दिल्ली, 01 जुलाई. सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानपुर को मध्य प्रदेश के भोपाल आर्थिक गलियारे से जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड राजमार्ग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक



मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

उन्होंने बताया कि योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर 117.7 किलोमीटर लंबे कानपुर-कबरई खंड को चार लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड राजमार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसे भविष्य में छह लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा. परियोजना पर 7,145.14 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. करीब दो साल में 242 किमी का प्रोजेक्ट पूरा होगा.

द्वारका एक्सप्रेसवे से वसंत कुंज तक बनेगी सुरंग सरकार ने राजधानी दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने के लिए 6970 करोड़ रुपये की लागत से आठ किलोमीटर लंबी छह लेन की सुरंग बनाने का निर्णय लिया है. दक्षिण दिल्ली के बीच तेज कनेक्टिविटी को बढ़ायेगी.

पूरे देश में लागू हुआ वी बी-जी राम जी

- न्यूनतम दैनिक मजदूरी 300, औसत मजदूरी 327.4
- जानिए ग्रामीण मजदूरों को क्या मिलेगा नया

नई दिल्ली, 01 जुलाई. केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पूरे देश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 लागू कर दिया है. नई व्यवस्था के लागू होने के साथ ग्रामीण रोजगार से जुड़े कई प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं.

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंगलवार को नई मजदूरी दरों का अधिसूचना जारी करते हुए बताया

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार देश के सभी 34 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और वितन क्षेत्रों में मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है. मंत्रालय का कहना है कि औसतन 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में मजदूरी दरों में 15 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है. वहीं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5 प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है. नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी भी बढ़ा दी गई है. पहले जहां 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध करने का प्रावधान था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है.

कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संशोधित मजदूरी दरें प्रभावी हो गई हैं. नई व्यवस्था के तहत औसत दैनिक मजदूरी 298.8 रुपये से बढ़ाकर 327.4 रुपये कर दी गई है. इस प्रकार औसतन 28.6

रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हुई है. इसके अलावा सरकार ने पूरे देश के लिए 300 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है, ताकि किसी भी राज्य या क्षेत्र में मजदूरी इससे कम न रहे.